भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *37
(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं

*37. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

श्री इटैला राजेंदर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर लोगों सहित सभी के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों की सुलभता एक बुनियादी अधिकार और मानव गरिमा का आवश्यक हिस्सा है तथा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर प्रत्येक टोल प्लाजा के पास सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के बावजूद, आम जनता यह पाती है कि कभी-कभार ही इनका उचित रखरखाव होता है और ये सुलभ हो पाते हैं;

(ख) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वे न केवल लिंगभेद किए बिना सभी को स्वच्छ शौचालय और पीने का पानी सुगमता से सुलभ कराएं बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि इन शौचालयों का वर्ष भर उचित रखरखाव भी हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ अब तक राज्यवार संस्वीकृत/व्यय की गई धनराशि सहित इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जहां तक राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजाओं के निकट सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का संबंध है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में वर्ष 2015 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परियोजना खंडों पर टोल प्लाजा के पास/पर पुरुषों/महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को किसी भी समस्या (जिसमें शौचालय/सार्वजनिक सुविधा भी शामिल है) की रिपोर्ट करने में सक्षम करने हेतु राजमार्ग यात्रा एप्लिकेशन हाल ही में विकसित किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने आंतरिक तंत्र के तहत और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति में सुधार के लिए, एनएचएआई वन (NHAI One) एप्लिकेशन में शौचालय की स्वच्छता का मॉड्यूल हाल ही में शुरू किया है, जिसमें शौचालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है और उनकी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एआई (AI) उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब तक, एनएचएआई वन (NHAI One) एप्लिकेशन पर 1300 से अधिक शौचालय ब्लॉकों को स्वच्छता की निगरानी के लिए पंजीकृत किया गया है।

इसके अलावा, टोल संग्रहण एजेंसियों के ठेकों की अनुसूची- II में शौचालय सुविधाओं के रख-रखाव के लिए सेवा स्तरीय समझौते (एसएलए) की आवश्यकता का विवरण दिया गया है, जिसके उल्लंघन पर प्रति माह प्रति चूक 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब तक टोल एजेंसियों पर लगभग 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

यह भी बताया गया है कि एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे 40-60 किलोमीटर के अनुमानित अंतराल पर सड़क-किनारे सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के विकास की योजना बना रहा है। इन सड़क-किनारे सुविधाओं पर सार्वजनिक शौचालयों को अनिवार्य सुविधा के रूप में रखा गया है। वर्तमान में देश भर में 455 सड़क-किनारे सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) का कार्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 90 डब्ल्यूएसए राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर कार्यरत हैं। उन 455 डब्ल्यूएसए की राज्य-वार संख्या जहां सार्वजनिक शौचालय प्रस्तावित हैं, अनुबंध-I में दिए गए हैं।

शौचालयों का निर्माण या तो राजमार्ग विकास के लिए सिविल ठेकों के मूल दायरे के हिस्से के रूप में या दायरे में बदलाव आदेश के रूप में किया जाता है और इसे राजमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ख) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने बताया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'स्वच्छता' राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जल एवं स्वच्छता सेवाओं का अधिकार सौंपा गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत नीति निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके मदद करता है ताकि स्वच्छता से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल किया जा सके। किसी भी शौचालय अवसंरचना की सही योजना और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए , आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों पर सलाह जारी की है जिसमें लिंग-विशेष (विशेष रूप से महिलाओं) की जरूरतों के लिए एक जांच सूची (चेकलिस्ट) भी दी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत, 31.12.2024 तक 67.57 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 6.52 लाख सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी)/ मूत्रालय बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय ने सूचित किया है कि विभाग ने पहले ही राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों , बाजारों, पर्यटन स्थलों , राजमार्गों, बस अड्डों आदि में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने का निर्देश दिया है। ग्राम पंचायतों के पास इन परिसरों के संचालन और रखरखाव की अंतिम जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत 2014-15 से अब तक 2.51 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।

स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के कार्यान्वयन में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था , जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है। खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने के बाद , स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण- II को 2020-21 से 2025-26 तक लागू किया जा रहा है , जिसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को बढ़ावा देना है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 11.80 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 37 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सड़क-किनारे सुविधा की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित सड़क किनारे सुविधाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	34
2.	असम	8
3.	बिहार	4
4.	छत्तीसगढ़	4
5.	गुजरात	45
6.	हरियाणा	48
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू और कश्मीर	20
9.	झारखंड	5
10.	कर्नाटक	17
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	48
13.	महाराष्ट्र	19
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	2
16.	ओडिशा	11
17.	पंजाब	35
18.	राजस्थान	58
19.	तमिलनाडु	22
20.	तेलंगाना	4
21.	उत्तर प्रदेश	44
22.	उत्तराखंड	3
23.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल योग	455

अनुबंध-II

लोक सभा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *37 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वच्छ भारत मिशन-शहरीके अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य	शौचालय निर्माण के लिए मिशन आबंटन		शौचालय निर्माण के लिए जारी धनराशि का विवरण	
		एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम- यू 2.0 (2021-2026)	एसबीएम- यू (2014-2021)	एसबीएम- यू 2.0 (2021-2026)
1	आंध्र प्रदेश	212.03	47.10	208.06	20.30
2	अंडमान और निकोबार	0.53	0.50	1.00	0.13
3	अरुणाचल प्रदेश	13.75	1.00	13.51	0.42
4	असम	84.26	14.20	84.26	3.54
5	बिहार	237.17	37.90	185.24	0.16
6	चंडीगढ़	2.98	3.30	3.08	0.83
7	छत्तीसगढ़	175.16	19.10	179.76	3.05
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	1.72	1.10	1.04	0.00
9	दिल्ली	55.31	10.00	30.23	0.00
10	गोवा	3.69	2.90	2.74	1.16
11	गुजरात	194.78	83.00	196.93	14.95
12	हरियाणा	67.28	28.50	57.06	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	14.92	2.20	14.16	0.55
14	जम्मू और कश्मीर	106.32	10.30	75.87	2.57
15	झारखंड	113.49	25.60	75.47	0.00
16	कर्नाटक	202.66	76.10	198.83	0.00
17	केरल	72.15	51.40	31.67	4.11
18	लद्दाख	-	0.70	-	0.18
19	मध्य प्रदेश	358.21	64.70	354.97	9.44

20	महाराष्ट्र	417.47	163.80	396.18	40.95
21	मणिपुर	47.74	2.50	46.97	0.63
22	मेघालय	5.98	1.90	5.05	0.48
23	मिजोरम	18.16	1.80	23.53	0.45
24	नागालैंड	26.78	8.17	26.48	2.04
25	ओडिशा	195.15	22.60	108.76	9.75
26	पुदुचेरी	8.35	1.45	5.66	0.58
27	पंजाब	87.11	33.50	72.91	15.69
28	राजस्थान	260.74	54.90	207.43	23.49
29	सिक्किम	2.69	0.50	2.89	0.13
30	तमिलनाडु	277.54	112.50	281.22	71.56
31	तेलंगाना	153.55	43.90	104.11	6.48
32	त्रिपुरा	68.77	3.10	27.18	0.00
33	उत्तर प्रदेश	553.31	143.40	540.59	31.94
34	उत्तराखंड	31.89	9.80	41.84	0.00
35	पश्चिम बंगाल	340.15	93.80	199.41	23.45

* मिशन आबंटन से अधिक धनराशि फ्लोटिंग फंड से जारी की जाती है।

अनुबंध-III

लोक सभा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *37 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण

पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय अंश (27.01.2025 तक)						
करोड़ रु में						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7.07	0.00	0.28	0.75	1.60
2	आंध्र प्रदेश	212.27	58.26	147.03	0.00	7.66
3	अरुणाचल प्रदेश	15.28	4.10	14.72	15.81	3.71
4	असम	276.81	256.78	214.45	389.77	24.95
5	बिहार	88.56	128.01	711.49	700.00	166.50
6	छत्तीसगढ़	68.43	0.00	177.54	83.98	0.00
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गोवा	0.23	15.32	25.19	19.61	0.00
9	गुजरात	312.56	171.37	53.63	109.61	150.00
10	हरियाणा	80.60	29.95	0.00	0.00	25.00
11	हिमाचल प्रदेश	23.62	41.95	38.28	42.00	22.09
12	जम्मू एवं कश्मीर	24.89	120.00	116.79	241.33	122.50
13	झारखंड	153.31	0.00	70.03	50.00	0.00
14	कर्नाटक	126.31	0.00	155.84	42.34	53.83
15	केरल	103.73	5.66	74.00	0.00	0.00
16	लद्दाख	2.71	3.56	1.28	5.75	2.55
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	291.48	334.48	184.56	113.39	121.05
19	महाराष्ट्र	276.75	0.00	0.00	110.45	115.82
20	मणिपुर	17.51	12.09	12.86	0.00	0.00

21	मेघालय	65.41	36.56	16.57	20.81	0.00
22	मिजोरम	14.05	13.22	9.84	5.00	4.42
23	नगालैंड	22.17	9.01	19.72	31.07	13.79
24	ओडिशा	58.92	0.00	0.00	46.52	74.61
25	पुदुचेरी	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	65.94	0.00	42.05	54.81	0.00
27	राजस्थान	229.26	275.93	288.78	69.43	73.35
28	सिक्किम	6.15	4.49	5.79	6.66	3.70
29	तमिलनाडु	162.89	0.00	78.48	239.74	75.00
30	तेलंगाना	46.86	0.00	0.00	14.18	0.98
31	त्रिपुरा	24.33	17.14	28.28	35.79	18.80
32	उत्तर प्रदेश	800.32	370.59	910.23	2506.71	458.29
33	उत्तराखंड	50.69	14.25	37.29	63.75	4.86
34	पश्चिम बंगाल	261.31	135.45	406.01	720.00	0.00
	कुल	3892.18	2058.15	3842.95	5739.25	1545.06